States will follow suit is a matter to be decided, after the initial experiment is found to be successful.

Shri Shree Narayan Das: May I know whether the Central had made a beginning in this connection? I would like to know whether any officer of the Finance Ministry was deputed or entrusted with the task of studying any new measures that are being tried in different countries?

Shri T. T. Krishnamachari: I am not able to say categorically yes or no; I would like to have notice.

छावनियों का विकास

*१३२६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री २६ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छावनियों के विकास के लिये जिस कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा था क्या इस बीच उसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस स्वीकृत कार्यक्रम की एक प्रति टेबल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा उपमन्त्री (सरदार मजीठिया): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सुझाव वित्त मन्त्रालय द्वारा विचाराधीन हैं और उनके शीघ्र पूरा होने की आशा की जाती है ।

श्री भक्त दर्शन : यह प्रश्न एक वर्ष से विचाराधीन कहा जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में इतनी देरी होने का क्या विशेष कारण है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि २६ मई, १९५७ को पूछे गये सवाल के जवाब में सभा-पटल पर रखे गये एक स्टेटमेंट में बताया गया था, इस का विशेष कारण यह है कि सारा खर्चा छ: करोड़ है और इस वक्त यह समझा जाता है कि यह खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार छः करोड़ रुपये के खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती है । क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छावनियों के विकास के लिये कितनी रकम निश्चित की गई है ?

सरदार मजीठिया : पिछले साल, १९५६-५७ में, ३० लाख रुपया दिया गया था और इस वर्ष ५५ लाख रुपया रखा गया है इन कामों के लिये ।

सरदार अ० सिं० सहगल : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ कारणवश यह कार्य शीघ्र नहीं हो सकता है । कौन कौन से ऐसे कारण हैं, जिन के कारण यह कार्य नहीं हो सकता है ? क्या मंत्री महोदय इस की व्याख्या करने की कृपा करेंगे ?

सरदार मजीठिया : मुल्क की जो फ़ाइनेंशियल पोजीशन है, वह तो माननीय सदस्य को मालूम ही है । उस को देखते हुये यह कार्य शीघ्र नहीं किया जा सकता है ।

श्री खाडीवाला : छावनियों के विकास के लिये प्रान्तीय सरकारों के जो कायदे हैं, उन को लागू कर उन को सहूलियत देने में क्या आपत्ति है ?

सरदार मजीठिया : पांच छः दिन हुये, इस के मुताल्लिक जवाब देते हुये मैं ने कहा था कि हम एक अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं । उस पर विचार हो रहा है ।

Shri Ayyakkannu: May I know whether there is any proposal under this

scheme to provide quarters for all married officers?

Sardar Majithia: Housing also forms part of the plan. But I cannot say off-hand how much has been allotted for that.

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई रकम निश्चित की गई है जिसके अन्तर्गत छावनियों के विकास के लिए रुपये हर साल मंजूर किए जायेंगे ?

Sardar Majithia: As I said, we have decided that we cannot give a specific amount for the Five Year Plan, but we will be allotting on a year to year basis for this purpose. I have already stated that during 1956-57, we have allotted Rs. 30 lakhs and during the current year Rs. 55 lakhs.

द्वादश-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण पत्र

*१३२७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि द्वादश-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्रों में पूंजी लगाने के लिये आवश्यक फार्म अब तक छापे नहीं गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). The 12-Year National Plan Savings Certificates were under print and have been made available at the post offices since the first week of this month.

Pandit D. N. Tiwary: For the last three or four months several people have returned from post offices without depositing money in National Savings Certificates. May I know whether any estimates have been made as to how much money has been returned. People went to the post offices to deposit money; but they could not because there was no form to deposit.

Shri T. T Krishnamachari: As I said, the decision to issue these Certificates was taken in the second week of May. The issue of these Certificates was announced by me in my Budget speech on the 15th of May. Our Securing Printing Press could not cope with the work that they had and they were not able to print these Certificates. But, the Post offices had made arrangements to issue temporary receipts against any applications that they receive. I have not got the details with me of any case where the Post office refused to issue temporary receipts. It is quite likely that people did not like the temporary receipts and took their money back. I am not in a position to say how much was taken back. It is undoubtedly a fact that these Certificates were not ready largely because of the timing of the decision to issue the Certificates and the natural lag that exists between the time when the decision is taken and the implementation for physical reasons.

Shri M. L. Dwivedi: There was a recent announcement by the Government that Cash Certificates will be paid by postmen in the villages Have the Government any information by what time this scheme will be launched?

Shri T. T. Krishnamachari: I require notice.

Shri Kamalnayan Bajaj: With a view to spreading saving habits even in the villages, may I know if the Finance Minister has considered giving some sort of a commission for those who can sell these Certificates, in the rural areas specially?

Mr. Speaker: How does that arise out of this question. It relates to scarcity of forms.